



भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI)
का दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र का मुखपत्र

मेहनतकश की आवाज़

बुलेटिन • संख्या-1 • वर्ष 1
अप्रैल 2019 • तीन रुपये • आठ पृष्ठ

अब विकल्प मौजूद है!

मज़दूरों, मेहनतकशों और ग़रीब किसानों
ने बनायी अपनी इंक़लाबी पार्टी

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी 2019 के लोकसभा
चुनावों में 7 सीटों पर खड़े करेगी अपने उम्मीदवार

दिल्ली और हरियाणा में दो-दो सीटों पर लड़ेंगे मज़दूर उम्मीदवार

मज़दूर-मेहनतकश साथियो! हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक चुनावों में हमारे पास चुनने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, इनेलो आदि सभी पूंजीवादी चुनावी पार्टियां मालिकों और ठेकेदारों के चन्दे पर चलती हैं। इन पार्टियों का सारा पैसा पूंजीपतियों से आता है। ऐसे में, वे हमारे हितों और ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती हैं। चूंकि कोई विकल्प मौजूद नहीं था, इसलिए हर चुनाव में हम इस या उस मालिकों-ठेकेदारों की पार्टी को वोट दे आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है! नवम्बर 2018 में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान आदि राज्यों से आये मज़दूरों, मेहनतकशों और ग़रीब किसानों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने एक नयी इंक़लाबी पार्टी का

निर्माण किया है: भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी यानी Revolutionary Workers' Party of India (RWPI)।

यह पार्टी किसी भी रूप में मालिकों, पूंजीवादी घरानों, ठेकेदारों, प्रापर्टी डीलरों, दलालों से कोई चन्दा नहीं लेती है। यह पूरी तरह से मज़दूरों और मेहनतकशों के चन्दे पर चलती है। चूंकि यह मज़दूर वर्ग के राजनीतिक संगठनकर्ताओं द्वारा बनायी गयी पार्टी है और चूंकि यह पूरी तरह मज़दूरों-मेहनतकशों के सहयोग पर चलती है, इसलिए यही पार्टी हम मज़दूरों, आम मेहनतकश आबादी और ग़रीब किसानों के हितों की सेवा कर सकती है। ये हमारी पार्टी है! इसे हमने बनाया है! हम ही इसे चलाते हैं! यह हमारे ही चन्दे पर काम करती है! इसलिए यही हमारी नुमाइन्दगी कर सकती है!

क्या कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, भाकपा, माकपा, इनेलो, आदि पार्टियां हम मेहनतकशों के लिए कुछ कर सकती हैं?

मेहनतकश बहनो और भाइयो! ज़रा दिमाग़ पर ज़ोर डालिये! अगर कोई पार्टी टाटा, बिड़ला, अम्बानी, अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के चन्दों पर चलती है तो क्या वह हम मेहनतकशों के लिए कुछ कर सकती है? अगर कोई पार्टी तमाम व्यापारियों, कारखाना मालिकों, ठेकेदारों, प्रापर्टी डीलरों और दलालों से पैसे लेकर काम करती है, तो क्या वह हम मेहनतकशों के वर्ग हितों की सेवा कर सकती है? अगर कोई पार्टी बड़े धनी किसानों, कुलकों, फार्मरों और आदतियों से पैसा लेकर काम करती

(पेज 3 पर जारी)

मज़दूर पार्टी को वोट दो!
ठेकेदारी को चोट दो!

मज़दूर पार्टी को वोट दो!
पूँजीवाद को चोट दो!

मेहनतकश ने ठाना है!
RWPI को जिताना है!

लोकसभा चुनाव में बवाना के मजदूरों-मेहनतकशों का एकमात्र विकल्प: भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी को जिताओ!

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पिछले साल 17 मजदूर जलकर मर गए थे। मरने वालों में अधिकतर महिला मजदूर थीं। इनमें एक बच्ची और एक गर्भवती महिला भी थी। इस मौत के तांडव के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर बह निकला और 3 मार्च को मजदूरों ने बवाना बन्द भी किया। लेकिन आज तक फैक्टरियों में आग लगना बन्द नहीं हुआ है। हर साल बवाना में करीब 450 फैक्टरियों में आग लगती है और इनमें से कई हादसों में मजदूर जलकर मर जाते हैं। फैक्टरियों में काम करते वक्त भी मजदूरों के खून को रोज-रोज फैक्टरियों में जलाकर उन्हें एक धीमी मौत दी जाती है। महिला मजदूर इन फैक्टरियों में महज 4000 से 5000 रुपये में घण्टों काम करती हैं। पुरुष मजदूरों को 12 घंटे काम करने के बाद महज 7000 से 9000 रुपये के बीच ही वेतन मिलता है। ऊपर से अक्सर मजदूरों का पैसा ठेकेदार लेकर भाग जाता है। श्रम कानून का खुला उल्लंघन होता है, न तो मजदूरों के काम के घंटे की कोई सीमा है, न न्यूनतम वेतन मिलता है। फैक्टरी एक्ट के अनुसार सुरक्षा नियमों का भी खुला उल्लंघन होता है। बवाना के पांचों सेक्टर में मजदूरों की जिंदगी नर्क है जहां लेबर इंस्पेक्टर और फैक्टरी इंस्पेक्टर द्वारा जांच के नाम पर महज जुबानी जमा खर्च होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और श्रम विभाग मालिकों की गोद में बैठा हुआ है और खुद मालिकों के लिए ही काम करता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने सरेआम सरासर झूठ बोलते हुए कहा कि दिल्ली में केवल 160 कारखानों में श्रम कानून नहीं लागू हो रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बवाना के हजारों कारखानों में कोई श्रम कानून लागू नहीं होता है।

मैट्रो विहार या बवाना के आसपास गाँव में रहने वाले मजदूरों की जिंदगी भी बेहाल है। मैट्रो विहार और बवाना जेजे कॉलोनी दिल्ली में जगह-जगह झुगियां उजाड़कर बसाई गई थी। परन्तु अभी तक भी हालत यह है कि पीने का पानी लोगों को खरीदना पड़ता है और इलाके में केवल उन घरों में पानी की सुविधा है जहां पर लोगों ने सम्मर्सिबल मोटर लगाए हैं।

पूरे बवाना में अस्पताल नहीं है। सबसे करीब नरेला में एक डिस्पेंसरी है जहां रोज़ डॉक्टर नहीं बैठता है। जन-यातायात की सुविधा यहाँ न के बराबर है केवल दो बसों का रूट ही लोगों को दिल्ली से जोड़ता है। किसी भी किस्म के सरकारी दफ़्तर बवाना की जनता के पास नहीं है। इस हालत में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के सांसद ने केवल

बस स्टैंड के सामने एक ओपन जिम बनवाया है और रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर पैसा खर्च किया है! उन्होंने मजदूरों की जिंदगी की हालत के बारे में चूँ तक नहीं किया। जब हमारे साथी फैक्टरियों में जलकर मरे तब भी तथाकथित दलितों के मसीहा सांसद डॉक्टर उदित राज ने इसपर कुछ न बोला। जाहिर है कि उदित राज जैसे दलित नेता केवल अमीर दलितों की बात करते हैं, ग़रीब मेहनतकश दलित की नहीं। मौजूदा सांसद उदित राज ने आग में मजदूरों की मौत पर न सिर्फ़ कुछ नहीं बोला बल्कि हर चुनावबाज पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। भाजपा की मेयर तो यह बोलते हुए टीवी पर पकड़ी गयी कि वह इस मसले पर कुछ नहीं बोलेंगी। ये पूंजीवादी चुनावी पार्टियां कुछ बोलेंगी भी नहीं क्योंकि बवाना के फैक्टरी मालिक ही चुनावबाज पार्टियों को चंदा देते हैं।

आज तक बवाना के मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज वह मजदूर विकल्प पैदा हो चुका है: भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, जिसे बनाने वालों में बवाना के मजदूर आन्दोलन के सक्रिय राजनीतिक संगठनकर्ता व नेता भी शामिल हैं! इसलिए बवाना के मजदूरों के सामने आज विकल्प बिलकुल साफ़ है: एक तरफ बवाना के मालिकों के चंदे पर चलने वाली और उनके लिए नीतियां बनाने वाली पार्टियां और दूसरी तरफ मजदूरों-मेहनतकशों की पार्टी, यानी, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी!

केवल मजदूर पार्टी (RWPI) का सांसद ही आपकी नुमाइन्दगी क्यों कर सकता है?

भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी का सांसद ही बवाना के मजदूरों के मुद्दों को लेकर लड़ सकता है। क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो अपना पूरा खर्चा आम मेहनतकश जनता के बीच से जुटाती है और किसी भी पूंजीवादी कम्पनी, देशी-विदेशी फंडिंग एजेंसी, एनजीओ से उसूलन एक भी पैसा नहीं लेती है। पार्टी का मकसद इस मुनाफा-आधारित पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा कर मजदूर राज स्थापित करना है। यह कार्य संसद के रास्ते ही नहीं हो सकता है लेकिन इस मकसद को अंजाम देने के लिए संसद के भीतर भी मजदूर वर्ग की आवाज़ पहुँचानी होगी। संसद के अंदर जिन देशव्यापी मुद्दों को लेकर सांसद संघर्ष करेगा वे बुलेटिन में पहले लेख में रखे गए हैं। इस लेख में हम उन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे कि बवाना

के मजदूरों के स्थानीय सवाल क्या हैं और उन सवालों पर सांसद क्या कर सकता है?

पहली बात, इस पार्टी को बनाने में वे कार्यकर्ता और मजदूर शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल 19 जनवरी को आग लगने पर केजरीवाल सरकार का घेराव किया था और सुरक्षा के इंतजामों को लागू करवाने के लिए 25 मार्च को हड़ताल की थी। इस साल भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के समर्थन से बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन ने 3 मार्च को श्रम कानूनों को लागू करवाने हेतु हड़ताल की थी। ज़रा सोचिए! अगर भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी का सांसद जीतता है तो क्या-क्या हो सकता है! फैक्टरी इलाके में श्रम कानून लागू करवाने का संघर्ष खुद सांसद करेगा और यह सुनिश्चित करवाने हेतु लड़ेगा कि फैक्टरियों में श्रम कानून लागू हों! ज़रा सोचिए! अगर मजदूरों के संघर्ष में मजदूर पार्टी का सांसद उनके नेता के तौर पर खड़ा हो तो हम उन सभी हकों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे जिनका मालिक और प्रशासन कि मिलीभगत के कारण मिल पाना असंभव हो जाता है। ज़रा सोचिए! जिन भी मुद्दों पर मजदूर और मालिक के बीच टकराव होगा यानी वेतन न मिलने से लेकर, काम से निकालने से लेकर श्रम कानून न लागू होने सरीखी सभी मांगें, उन पर आपका अपना मजदूर-वर्गीय सांसद आपके साथ खड़ा होगा।

मजदूर पार्टी (RWPI) का सांसद बवाना औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और मेहनतकशों के लिए क्या करेगा?

एक सांसद स्थानीय कामों के लिए साल में 5 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है। इस फंड से हमारी बवाना की मजदूर रिहायश में पीने के पानी कि सुविधा, स्कूल, पार्क, खेलकूद के इंतजाम, अस्पताल की बिल्डिंग सरीखे तमाम काम करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम सरकारी नीतियों को जनता तक पहुँचने में सांसद भूमिका निभा सकता है। हमारा मजदूर सांसद निम्न कार्य तो तत्काल शुरू करवा सकता है:

1. इस फंड से भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी का सांसद चुने जाने पर इलाके में पुस्तकालय खुलवाएगा, बच्चों के लिए शिक्षण-मनोरंजन क्लब खुलवाएगा।

2. राशन की पर्याप्त दुकानें खुलवाएगा जहां सस्ता राशन मिलता हो।

3. इलाके में तत्काल डिस्पेंसरी खुलवाएगा जहां डॉक्टर हर दिन बैठेगा व आगे चलकर

अब विकल्प मौजूद है!

(पेज 1 से जारी)

है, तो क्या वह गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों की खातिर कुछ कर सकती है? **इन सबका जवाब है: नहीं! क्यों? क्योंकि दोस्तो पुरानी कहावत है कि जो जिसका खाता है उसी का बजाता है! अगर कोई पार्टी पूंजीपति वर्ग के ही किसी हिस्से जैसे कि बड़ी कम्पनियों, मंझोले और छोटे कारखाना मालिकों, बड़े दुकानदारों, ठेकेदारों, दलालों, प्रापर्टी डीलरों, धनी किसानों, कुलकों, फार्मरों, आदतियों, नौकरशाहों से, चन्दे लेकर काम करती है, तो फिर वह हमारी नुमाइन्दगी कैसे कर सकती है? क्या इतनी सामान्य बात समझना मुश्किल है?** हम सभी जानते हैं कि ये पार्टियां हमारे पास तो पांच साल में केवल वोट लेने आती हैं, लेकिन सेवा ये गांव और शहर के बड़े, मंझोले और छोटे पूंजीपति की ही करती हैं। इन सभी को ये पूंजीपति ही पैसा देते हैं! यानी चुनावों में हारे कोई भी मगर जीतते मालिक, पूंजीपति, ठेकेदार, दुकानदार ही हैं! **क्यों? क्योंकि अब तक हम मजदूरों-मेहनतकशों की अपनी कोई क्रान्तिकारी पार्टी ही नहीं थी।**

नकली लाल झण्डे वाली भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन, एसयूसीआई जैसी पार्टियां मजदूर वर्ग का नाम लेकर उन्हीं से गद्दारी करती हैं। इनकी ट्रेड यूनियन मजदूरों के हितों का भाजपा और कांग्रेस की सरकारों से सौदा करती रही हैं। स्थानीय स्तर पर भी हर औद्योगिक क्षेत्र में इनकी यूनियन मजदूर संघर्षों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और कमीशनखोरी करती हैं। इन्हें देश के 93 प्रतिशत ठेका मजदूरों से कोई लेना-देना नहीं है। पक्के कर्मचारियों के भी एक बहुत छोटे हिस्से की ये नुमाइन्दगी करती हैं, जिन्हें आप कुलीन मजदूर/कर्मचारी वर्ग कह सकते हैं। उनके भी बड़े हिस्से से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये छोटे मालिकों, व्यापारियों, व्यवसायियों के दुख से दुखी रहते हैं। वास्तव में, ये सभी नकली कम्युनिस्ट पार्टियां केवल छोटे मालिकों, व्यापारियों, ठेकेदारों, व्यवसायियों, मंझोले व धनी किसानों के वर्ग की यानी कि निम्न-पूंजीपति वर्ग की ही सेवा करती हैं। मजदूरों का तो ये बस नाम लेती हैं। यही तो कारण है कि जब भी कोई वाम मोर्चा किसी राज्य में सत्ता में होता है, तो वह मजदूरों और गरीब किसानों पर वैसे ही लाठियां-गोलियां चलवाता है जैसे कि कांग्रेस व भाजपा की सरकारें चलवाती हैं। **पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार ने नन्दीग्राम, लालगढ़ और सिंगूर में यही तो किया था। क्या ऐसे नकली कम्युनिस्टों पर भरोसा किया जा सकता है? कभी नहीं!** ये तो आस्तीन के सांप हैं और इनसे तो सबसे ज्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।

आज हमारे पास एक नया विकल्प मौजूद है: **भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी (RWPI),**

यानी एक ऐसी पार्टी जो कि स्वयं हम मजदूरों और मेहनतकशों ने बनायी है और जो पूरी तरह हमारे और प्रगतिशील और न्यायप्रिय लोगों के चन्दों पर ही चलती है। यह किसी भी पूंजीवादी घराने, कम्पनी, पूंजीवादी चुनावी ट्रस्ट, फण्डिंग एजेंसी, एनजीओ से कोई भी फण्ड नहीं लेती। इसका नेतृत्व और सदस्य मजदूर वर्ग और आम मेहनतकश वर्गों से आता है, न कि धन्नासेठों, पूंजीपतियों, ठेकेदारों के घरों से। यही कारण है कि यही पार्टी सच्चे मायने में हमारी नुमाइन्दगी कर सकती है।

लोकसभा चुनाव 2019 शुरू होने में चन्द दिन बाकी हैं। दिल्ली व हरियाणा में 12 मई को मतदान है। आपको फैसला करना है साथियो! **क्या आप इस या उस पूंजीवादी चुनावी दल को वोट डालेंगे या अपनी मजदूर पार्टी को वोट डालेंगे? क्या आप चन्द रुपयों, या किसी सामान के बदले अपना वोट बेच देंगे और फिर अगले पांच साल तक पछताएंगे, या फिर आप अपनी मजदूर पार्टी को वोट देंगे और जिताएंगे? भविष्य आपका है! फैसला आपका है!**

भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, इनेलो, भाकपा, माकपा, आदि चुनावबाज़ पार्टियां क्यों नहीं कर सकतीं मजदूरों-मेहनतकशों की नुमाइन्दगी?

जैसा कि पहले बताया गया साथियो, जो जिसका खाता है, उसी का बजाता है। आइये देखते हैं कि किस पार्टी को कितना चुनावी चन्दा मिला है और किसने दिया है।

देश में सत्तासीन फ़ासीवादी भाजपा को सबसे ज्यादा 1034.27 करोड़ रुपये का चुनावी चन्दा मिला। इसमें से ज्ञात चन्दे का 95 प्रतिशत से भी ज्यादा बड़े पूंजीपतियों, कम्पनियों, मालिकों से आया है। इनमें सत्या चुनाव ट्रस्ट (एयरटेल लि., डीएलएफ बिल्डर, हीरो मोटरसाईकिल, आदित्य बिड़ला ग्रुप, एस्सार कम्पनी, टॉरेण्ट पावर कम्पनी, आदि), प्रोग्रेसिव चुनाव ट्रस्ट (टाटा), एबी जनरल चुनाव ट्रस्ट (आदित्य बिड़ला), सिपला लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर कम्पनी, माइक्रो लैब्स आदि प्रमुख हैं। बड़े पूंजीपतियों के टुकड़ों पर पल रही भाजपा भला मजदूरों, मेहनतकशों और गरीब किसानों की सेवा क्यों करने लगी? ज़ाहिर है, कि नरेन्द्र मोदी की फ़ासीवादी सरकार खुले तौर पर देश की मेहनत और कुदरत को लूटने की छूट इन पूंजीपतियों को देगी और देती रही है। यही तो वजह है कि सारे श्रम कानून समाप्त किये जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर नोटबन्दी और जीएसटी से मजदूरों और मेहनतकश आबादी को बेरोज़गार बनाया गया ताकि उनकी औसत मजदूरी गिर जाये, मन्दी से निपटने के लिए पूंजीपतियों को बैंक में जमा जनता का धन लेकर गबन करने और भागने की इजाज़त दी गयी! स्वयं

भाजपा नेताओं-मन्त्रियों ने राफेल घोटाले से लेकर, फसल बीमा घोटाला, व्यापम घोटाला, स्टेशनरी घोटाला कर करोड़ों रुपये कमाये! ये पैसे की रंगत ही है जिससे कि आज भाजपा हत्या, बलात्कार, घोटालों, चोरी, डकैती जैसे आरोपों में फंसे सांसदों-विधायकों और मन्त्रियों की पार्टी बनी हुई है। सबसे ज्यादा करोड़पति भी भाजपा में ही हैं! क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा देश के गरीब मजदूरों, किसानों और आम मेहनतकशों की नुमाइन्दगी करेगी? **क्या टाटा, बिड़ला, अम्बानी, अडानी, जिन्दल, मित्तल जैसे बड़े पूंजीपतियों ने हज़ारों करोड़ रुपये का चन्दा भाजपा को समाज-सेवा करने के लिए दिया है? नहीं साथियो!** यह चन्दा इसलिए दिया गया है कि मोदी की फासीवादी सरकार पूंजीपतियों के हाथों देश की मेहनत और कुदरत को नंगई से बेच दे और भाजपा की मोदी सरकार ने यही किया है।

कांग्रेस को भाजपा से कहीं कम चन्दा मिला क्योंकि इस समय देश के पूंजीपतियों को मोदी की फासीवादी सरकार चाहिए जो कि मजदूरों के हक़-हुकूक को बेशर्मी से कुचले और उनके हर प्रतिरोध को भी बेरहमी से दबाये। इसीलिए कांग्रेस को भाजपा से पांच गुना कम चन्दा मिला, यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपया। लेकिन यह चन्दा भी लगभग उन्हीं पूंजीपतियों और मालिकों-ठेकेदारों ने दिया है, जिन्होंने भाजपा को भी चन्दा दिया। यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी! जीते चाहे भाजपा या कांग्रेस, मगर जीत पूंजीपति वर्ग की ही होगी और हार आम मेहनतकश जनता की ही होगी! वैसे भी कांग्रेस भारत के पूंजीपतियों की सबसे पुरानी और भरोसेमन्द पार्टी रही है। ऐसे में, भाजपा सरकार के खिलाफ़ भारी गुस्से के कारण यदि कांग्रेस के नेतृत्व में यदि किसी गठबन्धन की सरकार बनती है तो भी पूंजीपति वर्ग का ही राज चलेगा क्योंकि कांग्रेस भी भाजपा के समान बड़े पूंजीपति वर्ग की ही पार्टी है।

अपने आपको “आम आदमी” की पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी के चुनावी चन्दे का स्रोत देखें तो पता चल जाता है कि इसके ‘आम आदमी’ कौन हैं! आम आदमी पार्टी को भी सत्या चुनाव ट्रस्ट जिसे एयरटेल, डीएलएफ, आदित्य बिड़ला, एस्सार, हीरो जैसे कई बड़े पूंजीपति चला रहे हैं, ने भारी चुनावी चन्दा दिया है। ‘आप’ को कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपया चुनावी चन्दा प्राप्त हुआ है। इसमें बड़े पूंजीपतियों के अलावा दिल्ली के छोटे कारखाना मालिकों, प्रापर्टी डीलरों, बड़े दुकानदारों, ठेकेदारों, ज्यूलरी वालों, दलालों, ने मुख्य रूप से चन्दा दिया है। सही मायने में ‘आप’ दिल्ली के छोटे मालिकों, व्यापारियों, प्रापर्टी डीलरों, दलालों, ठेकेदारों की ही पार्टी है। स्वयं

(पेज 4 पर जारी)

मज़दूरों, मेहनतकशों और ग़रीब किसानों ने बनायी अपनी इंक़लाबी पार्टी

(पेज 3 से जारी)

इसके नेताओं व उनके रिश्तेदारों जैसे कि विकास गुप्ता, गिरीश सोनी आदि के दिल्ली में कारखाने चलते हैं। ज़रा सोचिये मज़दूर और मेहनतकश भाइयो और बहनो! क्या कोई कारखाना मालिकों और ठेकेदारों की पार्टी आपके हकों की बात कर सकती है? क्या वह आपकी नुमाइन्दगी कर सकती है? कभी नहीं!

इसी प्रकार नकली लाल झण्डे वाली भाकपा को 1 करोड़ 15 लाख, माकपा को 2 करोड़ 76 लाख रुपये चन्दा मिला। इन्हें चन्दे देने वाले लोगों में छोटे मालिक, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, स्थायी सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग और स्वयं इनके नेतागण शामिल हैं। ये पार्टियां बात मेहनतकश वर्ग की करती हैं, लेकिन इनके चन्दों का स्रोत दिखलाता है कि ये सेवा छोटे पूंजीपति वर्ग, मध्य वर्ग और धनी व मंझोले किसानों की करती हैं। ये सुधार के लिए लड़ती हैं, परिवर्तन के लिए नहीं और इसलिए कोई सुधार भी हासिल नहीं कर पातीं। साथ ही, जहां कहीं भी ये सत्ता में आती हैं, मज़दूरों और ग़रीब किसानों पर उसी प्रकार जुल्म करती हैं, जैसे कि कोई भी खुले तौर पर पूंजीवादी पार्टियां। नन्दीग्राम, सिंगूर और लालगढ़ में आम मेहनतकश जनता का वाम मोर्चा की सरकार द्वारा दमन इसी बात को सिद्ध करता है।

दलितों की रहनुमा बनने वाली बसपा की सच्चाई यह है कि इसके चन्दे का अधिकांश हिस्सा दलित जनता के बीच से पैदा हुए एक छोटे-से पूंजीपति वर्ग, निम्न पूंजीपति वर्ग और उच्च मध्य वर्ग से आता है। इसके चन्दों का स्रोत अज्ञात है क्योंकि यह 20 हजार से अधिक का चन्दा किसी एक व्यक्ति से नहीं लेती, और इसलिए यह अपने चन्दा देने वालों का नाम नहीं बताती। लेकिन सभी जानते हैं कि इनका चन्दा दलित नौकरशाहों, उच्च और मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारियों आदि से आता है। यह दलित आबादी का इस्तेमाल करते हुए दलित आबादी के मात्र 9 प्रतिशत, यानी कि दलित आबादी में से पैदा हुए पूंजीपति मालिक वर्ग, ठेकेदारों, नौकरशाहों आदि की सेवा करती है। साथ ही, जब यह सरकार में होती है तो यह अन्य पूंजीवादी घरानों की भी जमकर सेवा करती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान मायावती ने मुख्यमन्त्री के तौर पर किया था।

यही हाल सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पूंजीवादी चुनावबाज़ पार्टियों का है। इन सभी के चन्दे मुख्य रूप से बड़े पूंजीपति वर्ग, छोटे पूंजीपति वर्ग, धनी किसानों, मालिकों, ठेकेदारों, उच्च मध्यवर्ग से ही आते हैं। ऐसे में, ये हम मज़दूरों और मेहनतकशों की नुमाइन्दगी कर ही नहीं सकती हैं। इसीलिए हमने कहा कि अब तक चुनावों में मज़दूरों और मेहनतकश आबादी के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ऐसी कोई पार्टी ही नहीं है जो पूरी तरह उन्हीं के चन्दों

पर चलती हो, उन्हीं के द्वारा बनायी गयी हो। अब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है - भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी।

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) यानी मज़दूरों और मेहनतकशों की अपनी पार्टी

मज़दूर पार्टी का निर्माण नवम्बर 2018 में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान आदि राज्यों से आये मज़दूरों, मज़दूर आन्दोलन के राजनीतिक संगठनकर्ताओं और क्रान्तिकारी छात्रों-युवाओं ने किया। इस पार्टी का नेतृत्व और काडर मज़दूर वर्ग और आम मेहनतकश आबादी से और उनके राजनीतिक संगठनकर्ताओं के बीच से आते हैं।

यह मज़दूर पार्टी उसूलन किसी पूंजीवादी घराने, कम्पनी, एनजीओ, पूंजीवादी चुनाव ट्रस्ट, फण्डिंग एजेंसी से कोई पैसा नहीं लेती। यह केवल और केवल मज़दूर वर्ग, आम मेहनतकश आबादी और प्रगतिशील व्यक्तियों के बीच से व्यक्तिगत चन्दे लेकर अपने समूचे फण्ड को जुटाती है। यही कारण है कि यह पार्टी सच्चे मायने में ईमानदारी से मज़दूर वर्ग और आम मेहनतकश आबादी की नुमाइन्दगी करती है। यह पार्टी मज़दूर वर्ग का हिरावल दस्ता और समूचे मेहनतकश आबादी का नेतृत्वकारी कोर है। इस पार्टी का अन्तिम लक्ष्य है क्रान्तिकारी रास्ते से देश के सभी खेतों-खलिहानों, कल-कारखानों, और खानों-खदानों पर देश के ग़रीब किसानों और खेतिहर मज़दूरों, औद्योगिक व शहरी मज़दूरों और आम मेहनतकश आबादी का हक़ स्थापित करना और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें फ़ैसला लेने की ताक़त वाकई मज़दूर वर्ग और आम मेहनतकश आबादी के हाथ में हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी क्रान्ति को अंजाम देने और एक नयी समाजवादी व्यवस्था के निर्माण करने के कार्य में अभी एक लम्बा समय लगेगा। लेकिन तब तक क्या मज़दूर वर्ग कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आप, भाकपा, माकपा, इनेलो, आदि जैसी इस या उस पूंजीवादी या निम्न पूंजीवादी पार्टी का पिछलग्गू बना रहेगा? नहीं! क्या वह हर चुनाव में मालिकों-ठेकेदारों की इस या उस पार्टी को वोट दे आयेगा? नहीं! यदि ऐसा हुआ तो वह दिन ही कभी नहीं आयेगा जब कि देश के समूची सम्पदा पर देश के मेहनतकश वर्गों का साझा हक़ होगा और फ़ैसला लेने की ताक़त उनके हाथों में होगी। यदि हम इन पूंजीवादी चुनावी दलों को वोट देते रहे तो देश का पूंजीपति वर्ग मिलकर हमें लूटता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मज़दूरों और आम मेहनतकश आबादी की अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी हो, जिसका पूंजीपति वर्ग से कोई भी राजनीतिक या आर्थिक सम्बन्ध न हो और वह पूरी तरह से मज़दूर वर्ग

पर निर्भर हो, उसी के बीच मौजूद हो, उन्हीं के बीच से पैदा हुई हो और बनती हो। ऐसी पार्टी के तौर पर ही मज़दूरों-मेहनतकशों और उनके संगठनकर्ताओं ने भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) का निर्माण किया है।

अब विकल्प मौजूद है, दोस्तो! अब हमें मालिकों, धन्नासेठों, ठेकेदारों की राजनीतिक पार्टियों की पूंछ पकड़कर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है! अब हमारे पास अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी मौजूद है जो कि चुनावों समेत समाज और राजनीति के हर मंच पर हमारे हकों और हितों की नुमाइन्दगी कर सकती है। इस पार्टी को हमें बड़ा और ताक़तवर बनाते जाना है।

इस दिशा में पहला कदम यह है कि आप सभी एकजुट होकर आने वाले लोकसभा चुनावों में भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें! दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से साथी अदिति और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से साथी योगेश चुनाव में आपके उम्मीदवार हैं! एकजुट होकर इन्हें वोट दें और इनकी जीत को सुनिश्चित करें! साथ ही, हम सभी मज़दूर भाइयों और बहनों से अपील करेंगे कि अपने मज़दूर प्रतिनिधियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी के वालण्टियर बनें, उसका प्रचार करें, हर मज़दूर और मेहनतकश भाई-बहन को समझाएं कि अब हमारे पास विकल्प है और अब हमें उसे ही आगे लेकर जाना है! यदि अब भी हम जाति-धर्म देखकर, पैसे या किसी अन्य वस्तु के लालच में, या किसी अन्य लोभ में किसी पूंजीवादी दल जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, आप, इनेलो, बसपा आदि को वोट देते हैं दोस्तो, तो कल हमें शिकायत करने का कोई हक़ नहीं होगा! इसलिए चन्द रुपयों, किसी सामान या जाति-धर्म के लिए वोट करके पांच वर्ष के लिए अपने राजनीतिक अधिकार, अपने वोट के अधिकार का दुरुपयोग मत करिये! अपने मज़दूर प्रतिनिधि को चुनिये! ज़रा कल्पना करें कि यदि आपके इलाके में आपका अपना मज़दूर प्रतिनिधि सांसद होगा तो हम अपने हकों के लिए कितने बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। इसलिए एकजुट होकर भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी के मज़दूर उम्मीदवार को वोट दें, पार्टी के वालण्टियर बनें, हर तरह से उसका समर्थन करें, उसे चन्दा दें और उसका प्रचार करें।

मज़दूर पार्टी को वोट दो!

पूंजीवाद को चोट दो!

मज़दूर पार्टी को वोट दो!

ठेकेदारी को चोट दो!

मेहनतकश ने ठाना है!

RWPI को जिताना है!

गांव-देहात की मेहनतकश आबादी के हालात और उनके लिए भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी का एजेण्डा

जैसा कि हम जानते हैं, पूँजीवादी व्यवस्था में एक मजदूर को सिर्फ इतना दिया जाता है जिससे वह मर-मर कर ज़िन्दा रह सके। लेकिन आज के पूँजीवादी समाज में बेरोज़गारी, बेकारी, भुखमरी, गरीबी के चलते एक मजदूर को इतना भी नहीं मिल पाता कि वह उससे, खुद को और अपने परिवार को ज़िन्दा रख सके। आज अगर हम ग्रामीण मजदूरों के हालातों पर एक नजर दौड़ाएँ तो हम पाते हैं कि आज गाँव में रहने वाले मजदूर ज़्यादातर खेतिहर मजदूर, भट्ठा मजदूर, मिस्त्री या दुकान व मण्डियों में काम करने वाले मजदूर हैं। इस प्रकार का काम मजदूर अपने गाँव या अपने आस-पास के गाँव-शहर में करते हैं। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का काम कोई स्थायी काम नहीं होता। ये सभी काम सीज़न या मौसम के हिसाब से होते हैं। इसलिए उनको अपना ज़्यादा समय घर पर ही बिताना पड़ता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि गाँव में रहने वाली एक बहुत बड़ी मजदूर आबादी को गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोज़गारी में ही अपनी ज़िन्दगी गुज़ारनी पड़ती है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि इस प्रकार का काम मजदूरों को मिल भी जाता है तो किन हालातों में उनको यह काम करने पर मजबूर होना पड़ता है यह भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए।

गाँव के ईंट भट्ठा मजदूरों की हालत

भट्ठा मजदूरों की बात करें तो उन्हें बहुत बुरे हालात में काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। वे हर दिन कम से कम दस या उससे ज़्यादा घण्टे काम करते हैं। मजदूरों को यह काम ठेकेदारी प्रथा के तहत करना पड़ता है। भट्ठे के काम को करवाने के लिए भट्ठे का मालिक ही इसमें ठेकेदार की भूमिका निभाता है। यह काम भी कोई परमानेंट काम नहीं होता क्योंकि पूरे साल के दौरान भट्ठा केवल छः महीने ही चलता है बाकी के छः महीने वह बन्द रहता है। इसकी वजह से मजदूरों को छः महीने अपने घर बैठना पड़ता है। काम के दौरान जो एक मजदूर को उसकी सेफ्टी के लिए जो जरूरी समान दिया जाना चाहिए वह भी उनको नहीं दिया जाता। इन हालात में काम करने के बाद भी मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। बिना सेफ्टी के काम करते मजदूरों को जिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है उन बीमारियों के इलाज का कोई भी पैसा मजदूरों को नहीं मिलता। इसे पता चलता है कि भट्ठा मालिक द्वारा मजदूरों पर एक भी श्रम कानून लागू नहीं किया जाता।

इन मजदूरों का कहना है कि भयंकर बेरोज़गारी के कारण उन्हें इतने बुरे हालात में भी काम करना पड़ता है। अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनके बच्चे और वे भूखे मर जाएँगे। इसलिए उनको काम करने

पर मजबूर होना पड़ता है।

मनरेगा मजदूरों की हालत

इसी प्रकार के मिलते-जुलते हालात दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के भी हैं। अगर हम मनरेगा की जाँच-पड़ताल करें तो देखते हैं कि मनरेगा कानून के अनुसार 100 दिन काम की योजना है, लेकिन असल में ना तो मजदूरों को सौ दिन काम मिलता है और ना ही पूरी मेहनत का हिसाब मिलता है। कानून की किताबों में नये-नये कानून तो बनते हैं, किन्तु व्यवहार में कोई भी लागू नहीं होता। मेहनतकश वर्ग हर जगह शोषण का शिकार है। साथ ही 'डिजिटल इण्डिया' के नाम पर मजदूरों की दिहाड़ी मोबाइलों में डाली जाती है। अब सवाल यह है कि मजदूर अपना काम करेगा या फिर सिम कार्ड से अपने पैसे निकलवाने इधर-उधर भटकेंगे। दूसरी बात यह कि मोदी सरकार के आने के बाद से मनरेगा में नये-नये बदलाव कर दिये गये हैं, जिनके बारे में मजदूरों या उनकी यूनियन से बिना सलाह वेतन का भुगतान कार्यदिवस की जगह कार्य की पैमाइश के अनुसार किया जा रहा है। इस बदलाव से कई जगह ऐसा हुआ, जहाँ मजदूरों ने 8 घण्टे काम किया, लेकिन पैमाइश के अनुसार उनको भुगतान 150 रुपये ही मिले, जबकि हरियाणा में मनरेगा मजदूरी कार्यदिवस के अनुसार 281 रुपये हैं। वहीं अभी हाल की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी में सिर्फ 2.16 फीसदी की औसत बढ़ोत्तरी की है। छह राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मजदूरी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। 15 राज्यों में एक रुपये से लेकर पाँच रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

सरकारी दावों की बात करें तो मनरेगा कानून 2005 कहता है कि इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी बेरोज़गारी को कम करना। यानी कानून के तहत 1 वर्ष में परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन के रोज़गार की गारण्टी दी जायेगी। रोज़गार के पंजीकरण के 15 दिन के भीतर काम देने और काम ना देने की सूत में बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही गयी है। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी भी अलग-अलग राज्यों के हिसाब से तय की गयी है। हरियाणा में अभी ग्लिहाल 281 रुपये तय की गयी है।

मनरेगा के बजट की रकम भारी-भरकम होती है, जैसे 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ दिये गये। लेकिन इसकी ज़्यादातर रकम दूसरी योजनाओं में खर्च कर दी जाती है। वैसे भी पूरे देश में मनरेगा के तहत साल में सिर्फ 46 दिन औसत काम मिलता है। कागजों पर ज़रूर ये योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए कल्याणकारी लगती है, लेकिन असल मकसद है गाँव से आबादी का

पलायन रोकना। क्योंकि खेती में लगातार मशीनीकरण के कारण गाँव की गरीब आबादी में तेज़ी से बेरोज़गारी फैल रही है। ऐसे में कोई भी सरकार शहरी बेरोज़गारों की संख्या में इससे ज़्यादा बढ़ोत्तरी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वह शहरों में सामाजिक असन्तोष को बढ़ाएगा। इसलिए ऐसी योजना से सरकार चाहती है कि गाँव से आने वाले सम्भावित प्रवासियों को अर्द्धभुखमरी की हालत में, यानी सौ दिन के रोज़गार के साथ, अभी कुछ और समय तक गाँव में ही रोके रखा जाये। मनरेगा की योजना का बस यही मकसद था।

गाँव के गरीब मजदूरों व गरीब किसानों को क्या करना चाहिए?

ऐसे में गाँव-देहात की मजदूर आबादी के बीच पूरे साल के पक्के रोज़गार के लिए संघर्ष की शुरुआत की जानी चाहिए। चुनाव के समय पूरे पूँजीपति वर्ग की सेवा करने वाली सभी चुनावबाज़ पार्टियाँ इन मजदूरों के बीच वोट की भीख माँगने आती हैं और साथ में मजदूरों से बड़े लम्बे-चौड़े वायदे करती हैं ताकि मजदूरों का वोट अपने पक्ष में लिया जा सके। लेकिन असल में वह सत्ता में आने के बाद भूस्वामियों, धनी किसानों और पूँजीपतियों की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की सेवा करती हैं। चूँकि ये सभी पूँजीवादी चुनावबाज़ पार्टियाँ जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, सपा, बसपा बड़े, मझोले और छोटे पूँजीपतियों, भूस्वामियों, आदतियों, ठेकेदारों व धनी किसानों के धनबल से चलती हैं, इसलिए वह गाँव के गरीब किसानों और मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकतीं। यही बात समझकर देश के मजदूरों और गरीब किसानों ने अपनी नयी पार्टी बनायी है 'भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी' (RWPI)। यह पार्टी पूरी तरह मजदूरों व गरीब किसानों के सहयोग व चन्दे से चलती है। इसका नेतृत्व मजदूर व मेहनतकश के आन्दोलन से ही पैदा हुआ है। यही कारण है कि गाँव के गरीब किसानों और मजदूरों के हकों के लिए केवल और केवल यही पार्टी लड़ सकती है। इसलिए आज **मजदूर पार्टी** गाँव-देहात के ग्रामीण मजदूरों की माँगों को लेकर मेहनतकश आबादी को संगठित कर रही है। आने वाले चुनावों में यदि **मजदूर पार्टी** (RWPI) का उम्मीदवार जीतकर संसद में जाता है तो वह निम्न माँगों की पूर्ति के लिए काम करेगा:

1. **जमीन का राष्ट्रीकरण किया जाये और जिन भी खेतों को जोतने का काम स्वयं किसान अपनी और अपने परिवार की मेहनत से नहीं करती, बल्कि नियमित तौर पर उजरती मजदूरों से करवाती है, उसका सामूहिकीकरण कर**
(पेज 7 पर जारी)

भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी लड़ेगी आँगनवाड़ी महिलाकर्मियों को कर्मचारी का दर्जा दिलवाने का संघर्ष

देश भर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलने वाली समेकित बाल विकास परियोजना में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाकर्मि हैं। कुल मिलकर देखा जाये तो स्कीम वर्कर्स (आँगनवाड़ी, आशा व मिड-डे-मील वर्कर्स) की संख्या 1 करोड़ के करीब है। आँगनवाड़ी जैसी महत्वपूर्ण योजना को 'स्कीम' के दर्जे के तहत चला कर वाहवाही बटोरने वाली सरकारें इसकी ज़रूरत और इसकी कार्यप्रणाली पर कितना ध्यान देती हैं वह इसी तथ्य से साफ़ हो जाता है की भारत में दुनिया भर के कुपोषित बच्चों की एक-तिहाई आबादी है। 2018 में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर है। वहीं देश भर के आँगनवाड़ियों के हालातों पर अगर एक निगाह दौड़ाई जाये तो खुद सरकारी आंकड़ें ही इनकी स्थिति बयान कर देते हैं। 2016 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश की 13.7 फीसदी आँगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के साफ पानी का कोई इन्तज़ाम नहीं है। वहीं स्वच्छता की कसौटी पर सिर्फ़ 48.2 प्रतिशत केन्द्र मान्य पाये गए। 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 29,165 करोड़ रुपये की राशि आबण्टित की गयी है। लेकिन पिछले कई सालों की प्रवृत्ति देखें तो जितनी राशि आबण्टित की जाती है, असल में उतनी राशि कभी खर्च नहीं की जाती। तथ्य झूठ के बड़े-बड़े तिलिस्मों को भेद डालते हैं! मसलन, व्यय वित्त समिति (एक्स्पेंडिचर फाइनैन्स कमिटी) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में आँगनवाड़ी परियोजनाओं के लिए 1,23,580 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी थी, लेकिन 2012-17 के बीच खर्च की गयी राशि 78,768 करोड़ रुपये ही थी, जो स्वीकृत राशि का 64 प्रतिशत थी। 2016-17 के वित्तीय वर्ष की ही बात करें तो स्वीकृत राशि 30,025 करोड़ रुपये थी और खर्च की गयी राशि 14,561 करोड़, यानी स्वीकृत राशि का मात्र 48 प्रतिशत ही खर्च हुआ! बजट बनाते समय सरकारों के द्वारा अपने खूब गाल बजाए जाते हैं किन्तु आबण्टित राशि बहुत बार तो खर्च ही नहीं होती और यदि कुछ खर्च होती भी है तो बिना किसी पारदर्शिता के। कहना नहीं होगा कि बहुत सा पैसा एनजीओ-नेताशाही-नौकरशाही की ही भेंट चढ़ जाता है!

इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाली आँगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका योजना में कार्यरत 'वालण्टियर' के रूप में काम करती हैं। देश में तकरीबन 28 लाख आँगनवाड़ी महिलाकर्मि कार्यरत हैं। आँगनवाड़ी महिलाकर्मि एक ऐसी फौज है जिसकी हर शहर,

हर गाँव, हर इलाके में पहुँच है। सभी चुनावबाज़ पूँजीवादी पार्टियों ने इस ताकत का इस्तेमाल अपने हितों की लिये किया है। अपनी रैलियों की भीड़ बढ़ाने से लेकर वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया गया है। जुमलेबाज़ मोदी सरकार ने भी इसे ध्यान में रखते हुये स्कीम वर्करों के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी का जुमला पिछले साल के सितम्बर माह में ही उछाला था। 5 महीने में इस बढ़ोत्तरी की एक फूटी कौड़ी भी किसी आँगनवाड़ी महिलाकर्मि के बैंक खाते में नहीं पहुँची। वैसे भी आँगनवाड़ी महिलाकर्मि की असल माँग मानदेय बढ़ोत्तरी से ज़्यादा, कर्मचारी के दर्जे की है। 1975 से चल रही यह ज़रूरी योजना के तहत ज़मीनी तौर पर काम कर रही आँगनवाड़ी महिलाकर्मियों को न न्यूनतम मजदूरी मिलती है न ही ये किसी श्रम कानूनों के अंतर्गत आती हैं।

भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी (RWPI) स्कीम वर्करों (आँगनवाड़ी, आशा व मिड-डे-मील कर्मचारी) के पक्का किए जाने की माँग, उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की माँग का समर्थन करता है। यदि RWPI का प्रत्याशी जीत कर संसद में जाता है तो स्कीम वर्करों की इस माँग को व्यक्तिगत बिल के जरिये संसद में उठाने की घोषणा करता है। स्कीम वर्करों के लिये जुमले फेंकने वाली तमाम चुनावबाज़ पार्टियों ने आज तक कभी संसद में ऐसा सवाल उठाया तक नहीं है। ज़ाहिर है, इस मसले पर यदि यह पार्टियाँ स्कीम वर्करों को कर्मचारी का दर्जा दिये जाने के बिल के समर्थन में नहीं आती हैं तो मेहनतकश जनता के सामने खुद को ही नंगा करने का काम करेंगी। वैसे भी जिस देश में हर 5 में से एक नागरिक ग़रीब की श्रेणी में आता हो, वहाँ आने वाली पीढ़ी को पोषणयुक्त आहार दिये जाने का काम किसी 'स्कीम' के तहत क्यों है? RWPI का मानना है की इस स्कीम को बाकायदा नीति के रूप में चलाया जाना चाहिए न की किसी विशेष योजना के रूप में। जिस देश में बच्चे 'भात-भात' के रट लागते दम तोड़ देते हैं और देश की राजधानी में

तीन बच्चियाँ भुखमरी की कगार पर दम तोड़ देती हैं, वहाँ समेकित बाल विकास परियोजना को विशेष स्कीम के तहत चलाया जाना एक भद्दा मज़ाक है! ऐसे में आँगनवाड़ी महिलाकर्मियों को तय करना है की वो अपनी संख्या की ताकत का इस्तेमाल टाटा-बिड़ला-अम्बानी-अडानी के टुकड़ों पर पलने वाली पूँजीवादी चुनावबाज़ पार्टियों का मोहरा बनने के लिये करेंगी या मेहनतकश का स्वतन्त्र पक्ष खड़ा करने के लिये भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी का समर्थन करेंगी। तब का उम्मीदवार सांसद के तौर पर जीतने पर निम्न कार्यवाइयां तत्काल करेगा:

1) आँगनवाड़ी सेण्टरों पर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण इंसपेक्शन व महिलाकर्मियों का उत्पीड़न तत्काल बन्द करवाया जायेगा।

2) आँगनवाड़ीकर्मियों का मानदेय दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार आँगनवाड़ी वर्करों के लिए कुशल मजदूरों जितनी यानी रुपये 16,962 प्रति माह और हेल्परों की अकुशल मजदूरों जितनी यानी रुपये 14,000 प्रति माह करने के लिए तत्काल संघर्ष किया जायेगा।

3) विभाग द्वारा बिना किसी सुनवाई के निलम्बन या निष्कासन पर पूर्ण रोक लगायी जायेगी।

4) सरकार द्वारा जारी की गयी खाने की गुणवत्ता-सम्बन्धी घोषणा को तत्काल लागू करवाया जायेगा। सभी एनजीओ को मिले टेण्डरों को सार्वजनिक ऑडिट कराया जायेगा।

5) पैनल या लीव पर काम कर रहीं सभी बहनों को तुरन्त नियमित किया जायेगा।

6) प्रमोशन-सम्बन्धी नियमों को आँगनवाड़ी कर्मियों के लिए अनुकूल बनाया जायेगा।

7) आँगनवाड़ियों के अतिरिक्त चार्ज की व्यवस्था को तत्काल खत्म कर दिया जायेगा। खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जायेगा।

क्या आपको पता है?

मौजूदा संसद में करीब 83 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं! यानी कि वे खुद बड़े मालिक, पूँजीपति, ठेकेदार या दल्लाल हैं, जो कि मजदूरों से लूटी गयी अपनी दौलत के बूते संसद में पहुँचे हैं? क्या आप इतने नादान हैं कि आपको लगता है कि ये सांसद आपकी नुमाइन्दगी करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये आपके हितों की सेवा करेंगे? ज़रा सोचिये! केवल और केवल जनता के बल और धन पर खड़ी पार्टी ही यह कार्य कर सकती है, और वह पार्टी है **भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी (RWPI)। मजदूर पार्टी को वोट दें! मजदूर उम्मीदवार को जिताएँ! अपने हकों के संघर्ष को आगे बढ़ाएँ!**

लोकसभा चुनाव में बवाना के मज़दूरों-मेहनतकशों का एकमात्र विकल्प

आबादी के घनत्व के अनुसार अस्पताल खुलवाया जाएगा।

4. इलाके में मज़दूरों के रहने के लिए सुविधासम्पन्न और विशाल मज़दूर हॉस्टल बनवाए जाएंगे जहां वे मज़दूर रह सकें जिनके पास रहने की सुविधा नहीं है।

5. इन हॉस्टलों में सामुदायिक कैंटीन की सुविधा भी होगी जिसमें सस्ती दरों पर खाना मिलेगा।

6. इलाके की उजड़ी हुई सड़कें जन-निगरानी में बनवाई जाएंगी।

7. एम्बुलेंस और शव उठाने वाली गाड़ी की निशुल्क सेवा का इंतजाम किया जाएगा।

8. पीने के साफ पानी का इंतजाम किया जाएगा जिसके लिए पूरे इलाके में पानी की लाइनें बिछवाई जाएंगी।

9. पूरे इलाके में नालियों व जमा पानी को साफ़ करवाया जाएगा वा गटर की सफ़ाई ठीक प्रकार से होगी।

10. स्कूलों के लिए कम्प्यूटर खरीदे जाएंगे जहां ओपन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जाये। साथ ही युवाओं की ट्रेनिंग के लिए तकनीकी ट्रेनिंग केंद्र खोले जाएंगे।

11. खेल के सुविधासम्पन्न स्टेडियम व मोहल्लों में स्पोर्ट्स क्लब खोले जाएंगे।

12. पूरे इलाके के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी।

13. फैक्टरी इलाके में और रिहायशी इलाके में पर्याप्त संख्या में क्रेच (पालना घर) की सुविधा दी जाएगी, ताकि सभी महिला मज़दूरों के लिए सुविधा हो सके।

14. इलाके में जन सुनवाई केंद्र खोले जाएंगे जहां किसी भी समस्या को लेकर मज़दूर आबादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

15. बवाना को मुख्य शहर व उसके केन्द्रों से जोड़ने के लिए जन परिवहन की पूरी व्यवस्था की जायेगी, यानी पर्याप्त संख्या में बसें चलवाई जाएंगी।

16. तमाम सरकारी विभागों के दफ्तर

बवाना के रिहायशी क्षेत्र में ही खोले जाएंगे ताकि मज़दूरों को अपने छोटे-मोटे काम करवाने के लिए कई किलोमीटर दूर शहर के मुख्य केन्द्रों तक न जाना पड़े।

17. श्रम विभाग का एक कार्यालय बवाना में भी खुलवाया जायेगा।

ये वे कार्य हैं जिन्हें अगर एक मज़दूर वर्ग का प्रतिनिधि संसद में पहुंचे तो अपने लोकसभा क्षेत्र में करवा सकता है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों को चिन्हित करने के लिए भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी के सदस्य और वॉलंटियर इलाके में जांच-पड़ताल बैठक कर रहे हैं। बवाना के मज़दूरों को अपनी मज़दूर पार्टी का वॉलंटियर बनाना होगा और अपनी गली और मोहल्ले से लेकर हर स्तर पर इस लोकसभा चुनाव में पूंजीपतियों की इस या उस चुनावबाज पार्टी को चुनने की जगह मज़दूरों मेहनतकशों का स्वतंत्र पक्ष खड़ा करने में अपनी भागीदारी अदा करनी होगी। नहीं तो कल हमें अपनी किसी भी समस्या के बारे में शिकायत करने का कोई हक़ नहीं होगा।

गांव-देहात की मेहनतकश आबादी के हालात और उनके लिए भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी का एजेण्डा

(पेज 7 से जारी)

खेतिहर मज़दूरों व ग़रीब किसानों के समूहों को साझी खेती के लिए सौंप दिया जाये या उन्हें मॉडल सरकारी फार्मों में तब्दील कर दिया जाये। ज़मीन किसी की निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे किसी मनुष्य ने पैदा नहीं किया है। इसलिए इस पर समूचे देश का साझा हक़ है।

2. सभी खेतिहर मज़दूरों के कार्य को श्रम कानूनों के मातहत लाया जाये और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के उपयुक्त ढाँचे का निर्माण किया जाये।

3. बिना काम के अधिकार के संविधान में महज़ जीने का अधिकार लिख देना जनता के साथ एक बेशर्म धोखा है। काम के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाये। इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किया जाये और 'भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी अधिनियम' पारित किया जाये, जिसके तहत साल भर के पक्के रोज़गार की गारण्टी सरकार ले अथवा प्रति माह रु. 10,000 बेरोज़गारी भत्ता दे।

4. वस्तु के रूप में मज़दूरी के भुगतान पर पूरी रोक लगायी जायेगी और हर उद्योग में

मज़दूरी के भुगतान की नियत मासिक तिथि तय की जायेगी।

5. गाँवों में साफ़ पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

6. शौचालयों समेत साफ़-सफ़ाई की पूरी व्यवस्था की जायेगी।

7. समस्त सुविधायुक्त अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

8. विभिन्न प्रकार के समारोहों के लिए सुविधासम्पन्न सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

9. गाँव की ग़रीब आबादी के लिए निशुल्क पुस्तकालयों और व्यायामशालाओं का निर्माण किया जायेगा।

यदि मज़दूर पार्टी (RWPI) आने वाले

लोकसभा चुनावों में विजयी होती है, तो उसके सांसद इन सभी माँगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे। जो माँगें पूरी करना सांसद के अधिकार क्षेत्र में है, उन्हें तत्काल पूरा किया जायेगा।

इसलिए हम सभी ग्रामीण मज़दूर व ग़रीब किसान भाइयों और बहनों से अपील करते हैं कि:

1. मज़दूर पार्टी (RWPI) के वॉलंटियर बनें और उसकी प्रचार कार्रवाइयों में हिस्सा लें।

2. मज़दूर पार्टी को हर प्रकार का आर्थिक और भौतिक सहयोग दें।

3. मज़दूर पार्टी को सभी ग़रीब मज़दूर व ग़रीब किसान मिलजुलकर एकजुट होकर वोट दें।

क्या आपको पता है?

क्या आपको पता है कि मौजूदा संसद में 31 प्रतिशत से भी ज़्यादा सांसदों पर हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि जैसे गम्भीर मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार के मन्त्रियों तक पर हत्या व बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस व अन्य पूंजीवादी पार्टियों की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है। क्या आपको लगता है कि अपराधियों का जमघट बन चुकी ये पार्टियाँ संसद में आपकी नुमाइन्दगी करेंगी? असम्भव! इसलिए RWPI के मज़दूर उम्मीदवार को चुनें और संसद में अपनी स्वतन्त्र आवाज़ की नुमाइन्दगी को सुनिश्चित करें।

पूँजीपतियों की पार्टियों को जानो-1 भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है?

- भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े पूँजीपतियों की पार्टी है।
- भाजपा को 2017-18 में इन पूँजीपतियों से लगभग 1035 करोड़ रुपये का चन्दा मिला है।
- इस चन्दे के बूते भाजपा ने देश भर में अपने 600 नये फ़ाइव स्टार ऑफिस बनवाये हैं।
- भाजपा के कुल चन्दे के लगभग एक-चौथाई का ही स्रोत पता है। अन्य चन्दा अज्ञात स्रोतों से आया है।
- भाजपा चुनावी चन्दे के स्रोतों की रही-सही पारदर्शिता को भी समाप्त करने के पक्ष में है ताकि देश-विदेश के मालिक, ठेकेदार और दल्लाल उसे खुलकर चन्दा दें।

- सभी पार्टियों में से भाजपा में सबसे अधिक करोड़पति सांसद हैं, जो कि खुद ही मालिक व ठेकेदार हैं।
- सभी पार्टियों में से सबसे ज़्यादा अपराध के

आरोपी सांसद भाजपा

- सभी पार्टियों में से

अपराध करने के

सांसद व मन्त्री भाजपा

- भाजपा सरकार ने

किसी भी पार्टी की

घोटाले किये हैं जैसे

फसल बीमा घोटाला,

घोटाला, स्टेशनरी घोटाला, आदि।



स्त्रियों के खिलाफ सबसे अधिक आरोपी में हैं।

पाँच वर्षों के भीतर सरकार से ज़्यादा बड़े कि राफेल घोटाला, एनपीए घोटाला, व्यापम

- भाजपा के राज में जनता का पैसा गबन करने वाले सबसे अधिक अपराधी पूँजीपति देश छोड़कर भागे हैं जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी आदि। ज़ाहिर है, सरकार को सूचना के बिना ऐसे अपराधियों का भागना मुमकिन नहीं है।

- भाजपा के पांच साल के राज में करीब 5 करोड़ लोगों ने रोज़गार से हाथ धोया है और बेरोज़गारी पाँच दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी है, जिसका कारण भाजपा सरकार द्वारा देश की मेहनत और कुदरत की खुली लूट की छूट पूँजीपति वर्ग को दिया जाना।

- इन सभी कुकर्मों को छिपाने के लिए भाजपा अब 'पाकिस्तान-पाकिस्तान', 'हिन्दू-मुसलमान', 'मन्दिर-मस्जिद' चिल्ला रही है, देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, मेहनतकश जनता को बाँटने की कोशिश कर रही है।

क्या आप इस साज़िश का शिकार होंगे? या आप फासीवादी भाजपा की असलियत को पहचानेंगे?

क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से अम्बानी-अडानी-टाटा-बिड़ला आदि के फेंके टुकड़ों पर पलने वाली यह पार्टी देश के मज़दूरों, आम मेहनतकशों और निम्न मध्यवर्ग के लिए कुछ करेगी? नहीं! पूँजीपति वर्ग की आज के दौर में इस प्रमुख पार्टी की असलियत को पहचानिये और अपनी

पार्टी 'भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी' (RWPI) को वोट दीजिये!

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) की सभी मेहनतकशों व मज़दूरों से अपील

- मज़दूर पार्टी (RWPI) को वोट दें!
- मज़दूर पार्टी के वालण्टियर बनें!
- अपने इलाके में मज़दूर पार्टी की बैठक कराएं!
- मज़दूर पार्टी को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें!

सम्पर्क: 9873358124, 9289498250, 8685030984, 9812764062, पता: बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-94

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी हेतु सनी सिंह द्वारा प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, शाहदरा द्वारा मुद्रित. सम्पादक: सनी सिंह. बुलेटिन सं. 1, 5 अप्रैल 2019,

सम्पादकीय कार्यालय: बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-94